



2018:CGHC:32157-DB

-1-

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

ए. आर. बी. ए. संख्या 7/2017

भारत एल्यूमिनियम कं. लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर V I, स्कोप ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली में है, तथा अपना व्यवसाय पी.ओ. बाल्को नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से संचालित करती है।

---- अपीलकर्ता

---बनाम---

लार्क कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, ऋणानुबंध रोड नंबर 1, सेक्टर-19, न्यू पनवेल, जिला- रायगढ़ एम.एस.- 410206, महाराष्ट्र

-----उत्तरवादी

अपीलकर्ता कंपनी के लिए :- श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी-दावेदार के लिए :- श्री वी.आर. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अशोक मिश्रा, अधिवक्ता

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एवं

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे

सी.ए.वी. निर्णय

14/12/2018

माननीय न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा.

1. यह मध्यस्थता अपील, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "2015 का



अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13 के तहत, जिसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1996 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 37 के साथ पढ़ा जाए, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर द्वारा एमजेसी संख्या 12/2016 में दिनांक 9.1.2017 को पारित आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें एकमात्र मध्यस्थ द्वारा 10 जून 2013 को पारित अधिनिर्णय को रद्द करने की मांग की गई थी, जो अपीलकर्ता-कंपनी और उत्तरवादी-ठेकेदार के बीच 17 मई 2005 को निष्पादित अनुबंध के तहत उत्पन्न एक संविदात्मक विवाद के मामले में था।

2. अपीलकर्ता-कंपनी ने यहां सड़क निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की थी। उत्तरवादी - ठेकेदार, सफल निविदाकार होने के नाते, बातचीत के बाद, 11,75,00,000/- रुपये (ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मात्र) की लागत से सड़क के निर्माण कार्य को निष्पादित करने के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था। कार्य के भुगतान के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। पक्षकारों ने 17 मई 2005 को हुए समझौते के अनुसार विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित किया। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद, पक्षकारगण मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुईं, अपने दावे का विवरण, उसका उत्तर, साथ ही प्रति-दावा प्रस्तुत किया। पक्षकारगण को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई और कार्यवाही उपरोक्त संदर्भित अधिनिर्णय के पारित होने में समाप्त हुई। चूंकि दावेदार-ठेकेदार द्वारा किए गए कई दावों को अधिनिर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी, इसलिए इसे अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी। वही खारिज कर दिया गया है, इसलिए यह अपील दायर की गई है।
3. अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि दावेदार-ठेकेदार ने पहले ही 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' (संक्षेप में "एनसीसी") दे दिया था, यह सहमति और संतुष्टि का मामला था, इसलिए दावा मध्यस्थता योग्य नहीं था। अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा दावेदार-ठेकेदार पर किसी भी दबाव या ज़बरदस्ती या अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने की कोई विशिष्ट निवेदन



नहीं थी, इसे साबित करने के लिए बहुत कम विशिष्ट निर्णायक सबूत थे। हालांकि, मध्यस्थ ने विकृत रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि दावेदार-ठेकेदार ने ज़बरदस्ती के तहत 'एनसीसी' प्रस्तुत किया था, इसलिए, केवल दावेदार द्वारा 'एनसीसी' प्रस्तुत करने के आधार पर, दावे को मध्यस्थता योग्य नहीं माना जा सकता था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही अभिवचन और साक्ष्य के सख्त नियम मध्यस्थता कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, फिर भी, मध्यस्थता विवाद उठाने से पहले 'एनसीसी' पहले ही प्रस्तुत किए जाने के स्वीकृत तथ्य के आधार पर, दावा खारिज किए जाने योग्य था। मध्यस्थता कार्यवाही के दस्तावेजों का हवाला देते हुए, यह भी तर्क दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से एक समझौता हुआ था, इसलिए, यदि कोई विवाद था, तो उसका निपटारा हो चुका था, जिसके बाद भुगतान जारी किए गए थे। इसलिए, दावेदार किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं था। इस निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **मैसर्स पी.के. रमैया एंड कंपनी बनाम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1994 (supp) 3 SCC 126, मैसर्स पी.के. रमैया एंड कंपनी बनाम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1994 (supp) 3 SCC 83, चेयरमैन एवं एम.डी., एनटीपीसी लिमिटेड बनाम रेशमी कंस्ट्रक्शन्स, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (AIR 2004 SC 1330), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2015 (2) SCC 424 एवं ओ.एन.जी.सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम एएनएस कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड और अन्य (AIR 2018 SC 796) का निर्णयों पर अवलंब लिया है।**

अपीलकर्ता-कंपनी के अधिवक्ता की अगली निवेदन यह है कि जहां तक दावा संख्या 9, 10, 11 और 12 का संबंध है, मध्यस्थ ने न केवल विकृत रूप से कार्य किया बल्कि समझौते के दायरे से भी बाहर जाकर, विभिन्न मदों के तहत भुगतान का निर्देश दिया, बिना किसी अभिवचन के, बहुत कम सबूत के, कि संयंत्र मशीनरी, कार्यबल के निष्क्रिय रहने के कारण, दावेदार को कोई नुकसान हुआ जिसकी भरपाई हर्जाने के रूप में की जानी थी। मध्यस्थ ने, यह तर्क दिया जाता है, इस पहलू पर किसी भी सबूत पर विचार नहीं किया है और उन दावों



को यंत्रवत् रूप से उदारता के रूप में अनुमति दी है। समझौते के अनुसार कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि 31.3.2006 थी, जबकि कार्य केवल 2.7.2006 को पूरा हुआ था, यह कार्य का केवल छोटा हिस्सा था जो न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण पूरा नहीं हो सका था, जिसे बाद में दिसंबर 2006 के महीने में पूरा किया गया था। इस दृष्टिकोण से मामले पर विचार न करना और दावा संख्या 9 से 12 के तहत हर्जाना देना, इसलिए, पेटेंट अवैधता से ग्रस्त था और यह कदाचार के समान भी होगा, जो अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत हस्तक्षेप की गारंटी देगा। इस तर्क के समर्थन में कि जहां निष्कर्ष बिना किसी सबूत के निकाले जाते हैं, हस्तक्षेप अनुमेय है, **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम फेरो कंक्रीट**

कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड 2009 (12) SCC 1 एवं **ओएनजीसी लिमिटेड बनाम गारवारे**

शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AIR 2008 SC 456) के निर्णयों का अवलंब लिया है।

अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता की अगली निवेदन यह है कि वर्तमान मामले में, विवाद की सूचना 28.3.2007 को दी गई थी और यहां तक कि अधिनिर्णय 10.6.2013 को पारित किया गया था, जो मध्यस्थता अधिनियम 1996 में संशोधन अधिनियम 2015 के लागू होने से बहुत पहले था, इसलिए, अधिनिर्णय के साथ हस्तक्षेप के आधार से संबंधित प्रावधान की प्रयोज्यता के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है। **तूफान चटर्जी बनाम रंगन धर** (AIR 2016 Cal. 213) के निर्णयों पर अवलंब लिया गया है

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अगली निवेदन यह है कि समय अनुबंध का सार था क्योंकि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 9.2 के तहत स्पष्ट शर्तों के अनुसार, कार्य 31.3.2006 को पूरा किया जाना आवश्यक था, अनुबंध के खंड 13 के तहत प्रदान किए गए परिनिर्धारित नुकसान के अनुदान के लिए अपीलकर्ता का प्रति-दावा मंजूर किया जाना आवश्यक था, लेकिन उक्त दावे को अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में किसी भी जांच के बिना केवल अपीलकर्ता के आचरण से प्रभावित होकर खारिज कर दिया गया।

अगली निवेदन यह है कि जहां तक दावेदार के दावा संख्या 4 का संबंध है, जो बैंक गारंटी की वापसी से संबंधित है, उसे गलत तरीके से अनुमति दी गई है, बावजूद इसके कि ठेकेदार



निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहा था, यह एक स्पष्ट स्वीकृत तथ्य है। पार्टियों के बीच समझौते ने अपीलकर्ता-कंपनी को बैंक गारंटी भुनाने का अधिकार दिया था, जहां ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर काम का अनुपालन करने में विफल रहा था। इसलिए, दो बैंक गारंटियों में से, 1,50,000/- रुपये की एक बैंक गारंटी सही ढंग से भुनाई गई थी। चूंकि यह नकदीकरण सख्ती से अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार था, दावेदार-ठेकेदार इस राशि की वापसी का हकदार नहीं था।

अगली निवेदन यह है कि मध्यस्थ द्वारा दावेदार-ठेकेदार के दावा संख्या 5 को अनुमति देकर, अनुबंध की निर्धारित अवधि से परे ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के संबंध में संशोधित दरों को प्रदान करके पेटेंट अवैधता की गई है, अर्थात् 31.3.2006 के बाद निष्पादित कार्य। तर्क यह है कि उक्त दावा पक्षकारों के बीच समझौते की किसी भी शर्त से संबंधित नहीं है। दावा किसी अतिरिक्त कार्य के संबंध में नहीं था, बल्कि अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के संबंध में था और समझौते में किसी भी शर्त के अभाव में, ठेकेदार को अनुबंध के तहत काम की निर्धारित अवधि से परे उसके द्वारा किए गए काम के संबंध में उच्च या संशोधित दरों का दावा करने का अधिकार नहीं था, न ही मध्यस्थ संशोधित दरों पर अतिरिक्त भुगतान प्रदान कर सकता था।

4. उत्तर में, उत्तरवादी-ठेकेदार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थ द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की उचित जांच के बाद अधिनिर्णय पारित किया गया था, जो दावेदार के दावे के साथ-साथ अपीलकर्ता के प्रति-दावे से संबंधित था। मध्यस्थ ने व्यापक विचार किया है। पक्षकारों के दावे ने विभिन्न दावों के संबंध में अधिनिर्णय पारित किया है जो कानूनी रूप से स्वीकार्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित है और केवल इसलिए कि विभिन्न दावों पर दूसरे दृष्टिकोण की संभावना है, अधिनिर्णय को हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उस अधिनिर्णय के खिलाफ हस्तक्षेप अधिनियम 1996 की धारा 34 में विस्तृत रूप से गणना किए गए सीमित आधारों द्वारा परिचालित है। उत्तरवादी - ठेकेदार के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मध्यस्थता



अधिनिर्णय से निपटने के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले मौलिक सिद्धांत यह हैं कि मध्यस्थता अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और अवैधता के आरोप पर इसे नष्ट करने के बजाय अधिनिर्णय को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बाबूलाल पाठक** (AIR 1974 MP 179) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था।

दावेदार द्वारा 'एनसीसी' प्रस्तुत किए जाने के आधार पर सहमति और संतुष्टि और दावे की स्थिरता के मुद्दे पर, यह तर्क दिया जाता है कि 28.3.2007 को, दावे की एक सूचना दी गई थी जिसे बाद में 25.4.2007 को वापस ले लिया गया था और फिर उसके तुरंत बाद, 1.2 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया था, जो स्वयं दर्शाता है कि दावेदार के विभिन्न दावे हैं लेकिन असमान सौदेबाजी क्षमता के कारण, चूंकि बड़ी राशि अपीलकर्ता-कंपनी के हाथों में पड़ी थी, उसने शुरू में दावा वापस ले लिया था ताकि एक पर्याप्त राशि जारी की जा सके और बाद में, 26.12.2007 को, नया दावा आवेदन किया गया था जो दावेदार - ठेकेदार के वास्तविक दावे पर आधारित था। इसलिए, इसे सहमति और संतुष्टि का मामला नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां ठेकेदार को परिस्थिति में 'एनसीसी' प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था। मध्यस्थ ने इन परिस्थितियों को सिद्ध तथ्यों और पक्षकारों के आचरण के आधार पर ध्यान में रखा है, ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि कोई सहमति और संतुष्टि नहीं थी, लेकिन 'एनसीसी' का प्रस्तुतिकरण असमान सौदेबाजी क्षमता का परिणाम था जो अनिवार्य रूप से मध्यस्थ के विचार के लिए एक मामला है, जैसा कि **रामशरण और रामदयाल दाऊ कंपनी बनाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड** (1980 JLU 689) में अभिनिर्धारित किया गया था।

5. उत्तरवादी - ठेकेदार के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे इस बात पर जोर दिया है कि दावे की मध्यस्थता का मुद्दा मध्यस्थता कार्यवाही में नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि दावेदार द्वारा दी गई सूचना पर, अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और मामला नियुक्ति के चरण में इस न्यायालय तक भी पहुंचा था। मध्यस्थ जिसमें उच्च



न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। **आर.एल. कलथिया एंड कंपनी बनाम गुजरात राज्य** (2011) 2 SCC 400 और उसमें संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर अवलंब लेते हुए यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भले ही यह माना जाए कि अनुचित प्रभाव और ज़बरदस्ती के आरोप में विशिष्ट अभिवचनों की कमी के कारण मध्यस्थ द्वारा किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' प्रस्तुत किया गया था, वास्तविक दावा उठाने और ऐसे दावे के विवाद को मध्यस्थ को उसके अपने गुणों के आधार पर अधिनिर्णय के लिए संदर्भित करने पर कोई पूर्ण रोक नहीं है। वर्तमान मामले में, तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया था और इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के पहले दौर में मध्यस्थता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, इसलिए, अधिनिर्णय पारित होने के बाद इसे नहीं उठाया जा सकता था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 19 में निहित प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी नियमों, अभिवचनों और साक्ष्य से संबंधित प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं और यदि मध्यस्थ का अधिनिर्णय तात्विक साक्ष्य पर आधारित है, तो अधिनिर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि दावे के विवरण में विस्तृत रूप से कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किए गए हैं। यह तर्क दिया जाता है कि दावेदार के गवाह ए.डी. पात्रीकर के साक्ष्य में अनुचित प्रभाव का विशिष्ट साक्ष्य था, इसलिए, तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। **एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण** (AIR 2015 SC 620) पर अवलंब लिया गया है।

6. दावा संख्या 9, 10, 11 और 12 पर मध्यस्थ के निष्कर्ष पर हमले के जवाब में, उत्तरवादी - ठेकेदार के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा दायर शपथपत्र का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी कि निष्क्रियता के कारण, दावेदार-ठेकेदार को नुकसान हुआ था और, इसलिए, इस मद पर, मध्यस्थ ने सही रूप से मुआवजे का अधिनिर्णय किया, यह ध्यान में रखते हुए कि दावेदार ने उन संसाधनों



को जुटाया था जिनमें दिन-प्रतिदिन के खर्च शामिल थे। **मैसर्स अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम भारत संघ** 2007 Arb.W.L.J. 11 (SC) पर अवलंब लेते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही कोई मूल्य वृद्धि खंड न हो, कार्य अनुसूची की निर्धारित समय सीमा से परे कार्य की बढ़ी हुई/संशोधित दरें तब दी जा सकती हैं जब यह पाया जाए कि कार्य उन कारणों से पूरा नहीं किया जा सका जो दावेदार के कारण नहीं थे।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
8. विचार के लिए उठने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या ठेकेदार का दावा इस कारण से कानूनन मान्य था कि उसने 'एनसीसी' प्रस्तुत किया था, ताकि यह कहा जा सके कि दावेदार सहमति और संतुष्टि के सिद्धांतों के लागू होने से विवाद उठाने से विबंधित है। अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मुद्दा स्वयं मध्यस्थता योग्य नहीं था और यह मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने योग्य भी नहीं था। तथ्यात्मक आधार पर, यह विवाद में नहीं है कि दावेदार-ठेकेदार ने एक 'एनसीसी' प्रस्तुत किया था, हालांकि पहले उसने 28.3.2007 को दावे की एक सूचना दी थी, जिसे बाद में 25.4.2007 को वापस ले लिया गया था। उसके तुरंत बाद, दावेदार के पक्ष में 1.2 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। हालांकि, बाद में, 26.12.2007 को, दावेदार ने मध्यस्थता की मांग करते हुए एक मुद्दा उठाया, जिसके बाद दिनांक 18.2.2018 को अपीलकर्ता द्वारा अनुबंध के खंड-17 के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई, यह भी विवाद में नहीं है कि दावेदार-ठेकेदार ने इस न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया था जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मध्यस्थ की नियुक्ति समझौते के खंड 17.1 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी। मध्यस्थता आवेदन संख्या 22/2008 में दिनांक 3.1.2011 को पारित आदेश के माध्यम से, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था। दावेदार ने दावे का विवरण दायर किया था और अपीलकर्ता ने उत्तर के साथ-साथ प्रति-दावा भी दायर किया था। उसके समक्ष पक्षकारगण द्वारा किए गए अभिवचनों



के आधार पर, एकमात्र मध्यस्थ ने, विभिन्न मुद्दों के बीच, एक विशिष्ट मुद्दा, वास्तव में पहला मुद्दा, विरचित किया कि क्या दावेदार के दावे, विशेष रूप से 16.4.2007 को हुई बैठक और 11.5.2007 को दावेदार द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' और दावेदार द्वारा सहमति और संतुष्टि के कारण 50 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति के आलोक में, दावेदार के आचरण के कारणों से बनाए रखने योग्य या वर्जित हैं। यह मुद्दा दावेदार के पक्ष में और अपीलकर्ता के खिलाफ तय किया गया था। मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि दावेदार को अपनी सूचना वापस लेने और 'एनसीसी' जारी करने के लिए मजबूर किया गया था और दावेदार तनाव में था और अपने द्वारा किए गए काम के बकाया की वसूली के लिए वैध चिंता रखता था।

9. अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करते समय इस निष्कर्ष को चुनौती देते हुए एक विशिष्ट आधार उठाया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ ने सही ढंग से माना कि दावेदार ने ज़बरदस्ती और दबाव के कारण 'NCC' पर हस्ताक्षर किए और जमा किए थे, जो अपीलकर्ता द्वारा डाला गया था और, इसलिए, विबंधन का कानून दावेदार को अनुतोष मांगने के रास्ते में नहीं आएगा।

10. अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान मामला सहमति और संतुष्टि का है और दावेदार द्वारा 'एनसीसी' जमा करने का तथ्य, अपने आप में, बिना किसी और बात के, अनिवार्य रूप से इसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि सहमति और संतुष्टि थी और ऐसे मामले में, यह मध्यस्थता योग्य नहीं होगा। उपरोक्त निवेदन की विवेचन करने के लिए, हम इस पहलू से संबंधित उन निर्णयों का संदर्भ लेना उचित समझते हैं जो समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।

मैसर्स पी.के. रमैया (उपरोक्त) के मामले में, एक मुद्दा उठा कि क्या दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हुआ था और इस कारण से, विवाद स्वयं मध्यस्थता योग्य नहीं था। स्वीकृत तथ्यात्मक आधार पर, लिखित में समझौता हुआ था। यह माना गया कि स्वीकार्य रूप से दावेदार ने माप की शुद्धता के साथ-साथ अंतिम निपटान को स्वीकार करते हुए लिखित रूप



में स्वीकार किया था और राशि प्राप्त की थी और, इसलिए, संदर्भ के लिए कोई मध्यस्थता विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। माननीय न्यायमूर्तिगण ने *दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम के.के. कर* (1974) 1 SCC 141, *भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम अमर नाथ भानु प्रकाश* (1982) 1 SCC 625 और *भारत संघ बनाम एल.के. आहूजा एंड कंपनी* (1988) 3 SCC 76 के मामलों में पहले के निर्णयों पर विचार किया। उपरोक्त मामलों में निर्णय तथ्यों पर अलग थे, जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणी से स्पष्ट होगा:-

"8. उन तथ्यों पर, इस न्यायालय ने माना कि यद्यपि अनुबंध की अंतिम संतुष्टि के रूप में कथित भुगतान किया गया था, फिर भी चूंकि उत्तरवादी ने दावे के निपटान को स्वीकार करते हुए कोई रसीद नहीं दी थी, भुगतान एकतरफा था, इसलिए विवाद अभी भी बना हुआ था और इसलिए यह मध्यस्थता योग्य विवाद था और संदर्भ वैध था। भानु प्रकाश के मामले में भी कोई पूर्ण और अंतिम निपटान नहीं हुआ था और भुगतान रसीद के तहत प्राप्त नहीं हुआ था। एल.के. आहूजा एंड कंपनी के मामले में, इस न्यायालय ने सामान्य कानून निर्धारित करते हुए माना कि यदि बिल विभाग द्वारा तैयार किया गया था, तो दावा कमजोर हो जाता है। वह नहीं था सहमति और संतोष का मामला बल्कि दावे की पूर्व अस्वीकृति के बिना परिसीमा के रोक की अभिवचन करने का मामला। इसलिए, उसमें दिया गया अनुपात बहुत कम सहायक है।".....

रेशमी कंस्ट्रक्शन्स (उपरोक्त) के एक अन्य मामले में, यह मुद्दा फिर से विचार के लिए आया। दावेदार के खिलाफ सहमति और संतोष साबित हुआ था या नहीं, इस प्रश्न की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच के बाद की गई थी।



पी.के. रमैया (उपरोक्त) में ऊपर संदर्भित निर्णय और उसमें संदर्भित अन्य निर्णयों पर फिर से विचार किया गया। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:-

"18. सामान्यतः, एक सहमति और संतोष अपने आप में मध्यस्थता खंड को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यदि विवाद यह है कि अनुबंध स्वयं अस्तित्व में नहीं है, तो मध्यस्थता खंड को लागू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन यदि यह माना जाता है कि अनुबंध जीवित है, तो मध्यस्थता खंड का सहारा लिया जा सकता है। [देखें भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता (AIR 1959 SC 1362) और मजाती जूट मिल्स बनाम ख्वालीरसा (AIR 1968 SC 522)।

19. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने टिप्पणी किया है, कि क्या अनुबंध का निर्वहन सहमति और संतोष से हुआ था या नहीं, यह अनुबंध से उत्पन्न होने वाला विवाद है और इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

20. फिर भी एल.के. आहूजा (उपरोक्त) में सब्यसाची मुखर्जी, जे., जैसा कि तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश थे, ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के अवयवों को इस प्रकार प्रतिपादित किया:

6. ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रश्नों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के जीवनराम इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ [एआईआर 1978 कल 228] के निर्णय में चर्चा की गई थी, जिसमें हम में से एक (सब्यसाची मुखर्जी, जे.) एक पक्षकार था और जिसने इन सभी प्राधिकारियों से चर्चा करने के बाद यह माना कि यह प्रश्न कि क्या उठाए जाने वाले दावे को परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था या नहीं,



अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आदेश के लिए सुसंगत नहीं था। इसलिए, इसके दो पहलू हैं। एक यह है कि क्या मध्यस्थता में किया गया दावा परिसीमा अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत परिसीमा द्वारा वर्जित है और दूसरा, क्या धारा 20 के तहत किया गया आवेदन दावा वर्जित है। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत संदर्भ के लिए एक वैध दावा होने के लिए, यह आवश्यक है कि एक मध्यस्थता समझौता होना चाहिए और दूसरे, मतभेद उत्पन्न होने चाहिए जिस पर विचाराधीन समझौता लागू होता है और, तीसरा, वह अधिनियम की धारा 20 में निर्धारित समय के भीतर होना चाहिए।

21. यह माना गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से इनकार नहीं किया गया था और दावे का दावा और उसका खंडन किया गया था, मामला मध्यस्थता योग्य होगा। टिप्पणी की गयी: -

"धारा 20 के अंतर्गत संदर्भ हेतु आवेदन करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रार्थी को किसी धनराशि की वैध मांग का अधिकार हो तथा उस अधिकार के संबंध में कोई विवाद या मतभेद हो। यह तथ्य सत्य है कि कार्य पूरा होने पर, भुगतान पाने का अधिकार सामान्य रूप से उत्पन्न होगा और यह भी सत्य है कि अंतिम बिल के निपटान पर, और भुगतान प्राप्त करने का अधिकार कमजोर हो जाता है लेकिन दावा बना रहता है और क्या यह बना रहता है, यह एक ऐसा मामला है जो मध्यस्थता योग्य है।

[जोर दिया गया]



22. इस मामले के इस पहलू पर जयेश इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) में भी विचार किया गया है जिसमें **एल.के. आहूजा** (उपरोक्त) का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"क्या कोई राशि देय है और अपीलकर्ता द्वारा किया गया दावा किस हद तक मान्य है, यह मध्यस्थ द्वारा विचार किए जाने वाले मामले हैं। वास्तव में, क्या अनुबंध पूरी तरह से काम कर चुका है और क्या भुगतान पूर्ण और अंतिम निपटान में किए गए हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाना है जब उसी के संबंध में कोई विवाद हो।"

23. मैसर्स पी.के. रमैया एंड कंपनी (उपरोक्त) में राशि बिना शर्त प्राप्त की गई थी। पूर्ण और अंतिम संतुष्टि को एक अलग रसीद में लिखित रूप में स्वीकार किया गया था। उस स्थिति में निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था:

"इस प्रकार दावों के अंतिम निपटान द्वारा सहमति और संतुष्टि है। बाद में लगाया हुआ प्रपीडन आरोप विवाद के निपटान, भुगतान की स्वीकृति और स्वेच्छा से दी गई रसीद से बचने के लिए एक बाद का विचार और एक तरीका है।"

इस बात पर और जोर दिया गया कि भले ही पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निपटारा हो जाए, अनुबंध उसके तहत उत्पन्न होने वाले विवाद के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए समाप्त नहीं होता है और इस सिद्धांत का हवाला देते हुए कि आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती, यह माना गया था:-

"27. भले ही पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निपटारा हो जाए, अनुबंध उसके तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्धारण के उद्देश्य के लिए समाप्त नहीं होता है, और, इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते को लागू किया जा सकता



है। हालांकि यह सख्ती से लागू नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस जमीनी हकीकत से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं कि जिन मामलों में एक ठेकेदार ने भारी निवेश किया है, वह नियोक्ता से बिलों के तहत राशि न लेने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि विभिन्न कारण जिनमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य व्यक्तियों के प्रति उसकी देनदारियों का निर्वहन शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पलड़ा भारी होगा। वे सामान्य रूप से तब तक पैसा जारी नहीं करेंगे जब तक कि 'नो डिमांड सर्टिफिकेट' पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं। इसलिए, प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है।

28. इसके अलावा, *necessitas non habet legem* एक पुरानी कहावत है जिसका अर्थ है आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। एक व्यक्ति को कभी-कभी सौदे के दूसरे पक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ सकता है जो एक मजबूत स्थिति में है।

29. हालांकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि ऐसा मामला बनाया जाना चाहिए और अधिनिर्णय प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष साबित किया जाना चाहिए।

30. इस स्तर पर, न्यायालय केवल इस प्रश्न से संबंधित होगा कि क्या विचारणीय मुद्दे उठाए गए हैं जिन्हें मध्यस्थों द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। "

अंत में, विभिन्न पत्राचारों सहित संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद, उस मामले में दी गई तथ्य स्थिति ने न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि मध्यस्थता समझौता बना रहता है, जैसा कि निर्णय के पैरा-39 में निहित है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-



"39. वर्तमान मामले में तथ्य स्थिति इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगी कि मध्यस्थता समझौता इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि:

(i) अंतिम बिल के संबंध में विवाद उसकी स्वीकृति से पहले उत्पन्न हुए थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसे प्रतिवादी द्वारा तैयार किया गया था लेकिन अपीलकर्ता द्वारा पूरी तरह से सहमति नहीं दी गई थी;

(ii) अपीलकर्ता ने यह निवेदन नहीं दी है कि प्रतिवादी द्वारा अंतिम बिल जमा करने पर यहां कोई बातचीत या समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा तैयार किए गए अंतिम बिल को प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया;

(iii) प्रतिवादी ने यहां अंतिम बिल का भुगतान प्राप्त करने के तुरंत बाद अपना विरोध दर्ज कराया और अपने दावों को दोहराया।

(iv) समझौते के खंड 52 की व्याख्या और/या अनुप्रयोग एक ऐसा विवाद गठित करेगा जो मध्यस्थ के विचार के लिए आएगा।

(v) पक्षकारों के बीच पत्राचार के प्रभाव का निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया जाना होगा, खासकर प्रतिवादी के इस दावे के संबंध में कि अंतिम बिल को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया गया था।

(vi) अपीलकर्ता ने कभी भी ऐसा मामला नहीं बनाया कि अनुबंध समझौते का कोई नवीनीकरण हुआ हो या अनुबंध समझौते को एक नए समझौते से प्रतिस्थापित किया गया हो। केवल ऐसी स्थिति में, जब एक नया समझौता बनाने का मामला बनता है, तो प्रतिवादी द्वारा उसी को चुनौती देने का प्रश्न उत्पन्न होता है।





(vii) अपीलकर्ता का आचरण से यह पता चलता है की उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.12.1991 को उत्तरवादी से सूचना प्राप्त होने पर उसे सीधे तौर पर खारिज नहीं किया गया था, बल्कि विवादों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था और मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग की गई थी।

(viii) केवल जब स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया था तब अंतिम बिल के निपटान की निवेदन उठाई गई थी।

(ix) उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रथम दृष्टया इस अर्थ में कि मध्यस्थ के समक्ष विचारणीय मुद्दे हैं ताकि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के प्रावधानों को लागू किया जा सके, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है

(x) अधिनियम 1940 के तहत मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार यद्यपि संदर्भ से उत्पन्न होता है, यह सामान्य बात है कि किसी दी गई स्थिति में मध्यस्थ अनुबंध समझौते के निर्माण सहित कानून और तथ्य के सभी प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है। (देखें प्योर हीलियम इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, 2003 (8) SCALE 553 में प्रतिवेदित किया गया है) ।

(xi) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामले [पी.के. रमैया एंड कंपनी (उपरोक्त) और नथानी स्टील्स (उपरोक्त)] से यह पता चलता है कि उनमें निर्णय इस तथ्य के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे कि मध्यस्थ खंड वाले अनुबंध समझौते को दूसरे समझौते से प्रतिस्थापित किया गया था। ऐसे प्रश्न पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में उसमें प्राप्त होने वाली तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार और निर्धारण किया जाना है।”



11. इन निर्णयों ने उस दृष्टिकोण को निर्धारित किया गया है जिसका पालन यह निश्चित करने के लिए किया जाना आवश्यक है कि क्या दावेदार का दावा मध्यस्थता योग्य है या नहीं या दूसरे शब्दों में, सहमति और संतोष का मामला बनने के कारण, दावेदार दावा करने से विबंधित है और इस प्रकार विवाद स्वयं मध्यस्थता योग्य नहीं है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनों के लिए भी, मामले के संपूर्ण तथ्यात्मक विवरण, पक्षकारों के बीच पत्राचार और उनके आचरण पर विचार किया गया था और निष्कर्ष केवल इस आधार पर या उसके खिलाफ नहीं निकाला गया था तथा अन्य उपस्थित सामग्री और परिस्थितियों पर विचार किए बिना कि 'एनसीसी' जारी किया गया था,
12. **आर.एल. कलाथिया** (उपरोक्त) के मामले में, पिछले निर्णयों का पुनः संदर्भ दिया गया, जिसमें एक ठेकेदार द्वारा 'अदेयता प्रमाण पत्र' (No Dues Certificate) जमा करने के कारण विवाद की मध्यस्थता-योग्यता (arbitrability) के संबंध में समान मुद्दे को स्वीकार किया गया। इस बात पर विचार किया गया कि दावेदार का एक वास्तविक दावा था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बहुत विस्तार से विचार किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने विबंधन (estoppel) के सिद्धांतों को लागू करते हुए, केवल इस आधार पर पलट दिया था कि दावेदार के किसी भी तथ्यात्मक विवरण/दावों पर ध्यान दिए बिना 'अदेयता प्रमाण पत्र' जारी किया गया था। इस तथ्यात्मक स्थिति को निम्नानुसार नोट किया गया था:-

"14. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हम अभिलेख पर मौजूद सामग्री से आश्वस्त हैं कि प्रस्तुत मामले में, अपीलकर्ता/वादी का भी एक वास्तविक दावा था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा बहुत विस्तार से विचार किया गया था और जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने वादी के किसी भी तथ्यात्मक विवरण/दावे पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय इसके कि उसने विबंधन (estoppel) के सिद्धांत पर विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को पलट दिया, हमने विचारण न्यायालय के



न्यायाधीश की विस्तृत चर्चा और अंतिम निष्कर्ष का सावधानीपूर्वक अवलोकन और विचार किया है।”

उपर्युक्त निर्णय में, यहाँ ऊपर संदर्भित अनेक निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के उपरांत, जो सिद्धांत सामने आए, उन्हें निम्नानुसार निर्धारित किया गया :-

“13. इस न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों से, निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

(i) केवल इसलिए कि ठेकेदार ने "अदेयता प्रमाण पत्र" (No Due Certificate) जारी किया है, यदि कोई स्वीकार्य दावा है, तो न्यायालय "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी करने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं कर सकता।

(ii) चूंकि यह आम बात है कि जब तक ठेकेदार द्वारा अग्रिम रूप से एक उन्मोचन प्रमाण पत्र (discharge certificate) नहीं दिया जाता, बिलों के भुगतान में आम तौर पर देरी होती है, अतः संविदा (contract) में ऐसा कोई खंड ठेकेदार को, ऐसे 'अदेयता प्रमाण पत्र' (No-claim Certificate) जमा करने के बाद भी, बाद की तारीख में वास्तविक दावे करने से रोकने के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं होगा।

(iii) किसी एक पक्ष द्वारा पूर्ण और अंतिम उन्मोचन वाउचर/रसीद (full and final discharge voucher/receipt) निष्पादित किए जाने के बाद भी, यदि उक्त पक्ष यह स्थापित कर पाता है कि वह अतिरिक्त राशि का हकदार है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त सामग्री है, तो वह केवल अंतिम बिल को 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' (without prejudice) उल्लेख करते हुए स्वीकार करने या 'अदेयता प्रमाण पत्र' (No Due Certificate) जारी करने के कारण ऐसी राशि का दावा करने से वर्जित नहीं है।”



13. हाल ही में **जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर** (उपरोक्त) 424, के मामले में एक निर्णय में, यह मुद्दा पुनः विचार के लिए सामने आया और उक्त मुद्दे पर विचार करते समय, ऊपर संदर्भित कुछ निर्णय भी पुनः विचार के लिए प्रस्तुत हुए। *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी* (2011) 12 SCC 349, के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रस्तुत मामले के तथ्यात्मक पहलू की जांच करने पर, इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गयाः"

"9. इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी, प्रपीडन, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक मात्र निवेदन पर्याप्त नहीं है और जो पक्षकार निवेदन देती है, उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना होगा। इस प्रकार देखते हुए, प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका में प्रासंगिक कथनों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव के थे:-

"(g) कि उक्त सर्वेक्षक ने, प्रतिवादी कंपनी के साथ मिलीभगत करके, उत्तरवादी कंपनी को याचिकाकर्ता को हुए इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने की अपनी पूरी देनदारी से बचाने के लिए, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, नुकसान का आकलन करने के लिए ज़बरदस्ती, अनुचित प्रभाव और दबाव के तरीके अपनाए और याचिकाकर्ता को दावा प्रपत्र (Claim Form) सहित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। प्रतिवादी कंपनी ने भी अपने कृत्यों और चूकों द्वारा तथा ज़बरदस्ती एवं अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके याचिकाकर्ता के उचित दावे को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता कंपनी को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें उक्त राशि के लिए पहले से तैयार एक उन्मोचन वाउचर (discharge voucher) भी शामिल था, जिसे करने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी को उक्त अवधि के दौरान व्याप्त अत्यधिक वित्तीय कठिनाई की अवधि में मजबूर किया गया था।





जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता कंपनी को 6,09,55,406/- रुपये के नुकसान को स्वीकार करने वाले एक पत्र सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और 28,79,08,116/- रुपये की वास्तविक नुकसान राशि के मुकाबले 5,96,08,179/- रुपये के दावे का निपटान करने के लिए मजबूर किया गया था, जो याचिकाकर्ता कंपनी के हितों के विरुद्ध था। उक्त पत्र और उपरोक्त पहले से तैयार उन्मोचन वाउचर में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने दावा राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनी को इसे एकतरफा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता कंपनी को प्रतिवादी कंपनी द्वारा दबाव और जबरदस्ती के तहत उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। उत्तरवादी कंपनी ने याचिकाकर्ता कंपनी को और धमकी दी कि वह उक्त राशि को पूर्ण और अंतिम रूप से स्वीकार करे अन्यथा उत्तरवादी कंपनी अग्नि बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी राशि का भुगतान नहीं करेगी। ऐसी ही मजबूर करने वाली परिस्थितियों में याचिकाकर्ता कंपनी को मजबूर किया गया और दबाव में स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए।”

उस मामले में दावेदार द्वारा दायर किए गए दावों पर विचार किया गया और यह माना गया कि दावेदार द्वारा उठाई गई निवेदन किसी भी विवरण और विशिष्टताओं से रहित थी और यह एक मात्र दावे के अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। आगे यह भी देखा गया कि उक्त मामले में, समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के समय या उसके तुरंत बाद कोई विरोध या आपत्ति नहीं उठाई गई थी और नोटिस स्वयं तीन सप्ताह के बाद दिया गया था और आगे यह भी कि दावेदार की वित्तीय स्थिति इतनी अनिश्चित नहीं थी कि उसके पास सुझाए गए नियमों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और यह राय बनाई गई थी कि



समर्पण पत्र का निर्वहन और हस्ताक्षर किसी अनुचित प्रभाव के कारण नहीं था बल्कि यह स्वैच्छिक था और किसी भी ज़बरदस्ती या अनुचित प्रभाव से मुक्त था।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि उस मामले में भी, न्यायालय द्वारा सभी उपस्थित परिस्थितियों, अभिवचनों पर विचार करके मामले की जांच की गई थी, ताकि यह तय किया जा सके कि 'नो क्लेम सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट/समर्पण पत्र' का प्रस्तुतिकरण ज़बरदस्ती, अनुचित प्रभाव या स्वैच्छिक और स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए गए विकल्प का परिणाम था या नहीं।

14. हाल ही में **ए.एन.एस. कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले के निर्णय पर इस बात को देखने के लिए विचार किया गया कि क्या इस निवेदन के विरुद्ध कि 'अदेयता प्रमाण पत्र/कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र' ज़बरदस्ती और दबाव का परिणाम था, सहमति और संतुष्टि (accord and satisfaction) हुई थी। *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन* (2011) 12 SCC 349, *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड* (2015) 2 SCC 424, *नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोधारा पॉलीफेब प्राइवेट लिमिटेड* (2009) 1 SCC 267 और *आर.एल. कळाथिया एंड कंपनी बनाम गुजरात राज्य* (2011) 2 SCC 400 के मामलों में पूर्व के निर्णयों का संदर्भ दिया गया और तथ्यों के आधार पर, यह अभिलिखित किया गया कि 'अदेयता प्रमाण पत्र' अनुबंधग्रहीता-कंपनी (contractee-company) द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उनके अनुरोध पर, ठेकेदार द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह भी पाया गया कि अनुबंधग्रहीता ने, एक महीने के अंतराल के बाद, ज़बरदस्ती और दबाव के आधार पर 'अदेयता प्रमाण पत्र' वापस ले लिया और नुकसान के लिए दावा किया गया। जो निष्कर्ष निकाला गया वह निम्नानुसार था:-

"25. स्वीकार्य रूप से, अनुबंधग्रहीता-कंपनी (contractee-Company) द्वारा 21.09.2012 को 'अदेयता प्रमाण पत्र' (No-Dues Certificate) प्रस्तुत किया गया था और उनके अनुरोध पर अपीलकर्ता-ठेकेदार (appellant-



Contractor) द्वारा 'पूर्णता प्रमाण पत्र' (Completion Certificate) जारी किया गया था। अनुबंधग्रहीता ने, एक महीने के अंतराल के बाद, अर्थात् 24.10.2012 को, प्रपीडन और दबाव के आधार पर 'अदेयता प्रमाण पत्र' वापस ले लिया और अनुबंध स्थल के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा 12.01.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से किया, अर्थात् 3 ½ (साढ़े तीन) महीने के अंतराल के बाद, जबकि अंतिम बिल (Final Bill) का निपटान 10.10.2012 को किया गया था। जब अनुबंधग्रहीता ने अपने सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया, तो अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए इतने विलंबित चरण में दावा करने का कोई औचित्य नहीं है, जो इस बारे में जरा भी संदेह पैदा करता है कि अंतिम बिल जमा करते समय ऐसे दावे का निपटान क्यों नहीं किया गया, वह भी तब जब अपीलकर्ता-ठेकेदार द्वारा अनुबंधग्रहीता पर कोई दबाव या प्रपीडन नहीं की गई थी। हमारे सुविचारित मत में, अनुबंधग्रहीता-कंपनी द्वारा उठाई गई निवेदन किसी भी विवरण और विशिष्टताओं से रहित है, और यह एक निराधार दावे के सिवा कुछ नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हो गया था और वास्तव में सहमति और संतुष्टि (accord and satisfaction) हुई थी, और हमारे विचार में कोई मध्यस्थता-योग्य (arbitrable) विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए, उच्च न्यायालय का अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था।”

15. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, जो सार्वभौमिक अनुप्रयोग का सिद्धांत उभरता है, वह यह है कि एक बार सहमति और संतुष्टि (accord and satisfaction) हो जाने पर, और एक दावे का पक्षों के बीच अंतिम रूप से निपटारा हो जाने पर, जिसके अनुसरण में



दावेदार ने स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और बिना किसी प्रपीडन, धोखाधड़ी या दबाव के 'अदेयता प्रमाण पत्र/कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र' (No Dues Certificate/ No Claim Certificate) प्रस्तुत किया हो, तो वह (दावेदार) ऐसा दावा पुनः उठाने से विबंधित (estopped) हो जाएगा। तथापि, किसी दिए गए मामले में सहमति और संतुष्टि हुई है या नहीं, यह मूलतः एक तथ्यात्मक विवाद होगा जिसे अभिवचनों, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों, समवर्ती परिस्थितियों, पक्षों के आचरण आदि के संदर्भ में तय करने की आवश्यकता होगी। उच्चतम न्यायालय के एएनएस कंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय और यहाँ ऊपर संदर्भित पूर्व के निर्णयों के आलोक में भी, विवाद की मध्यस्थता-योग्यता (arbitrability) का प्रश्न उस चरण पर भी उठाया जा सकता है जब कोई एक पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन करके विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग करता है। इसे मध्यस्थ के समक्ष भी उठाया जा सकता है, जिस स्थिति में, मध्यस्थ इस मुद्दे को एक तथ्यात्मक प्रश्न के रूप में तय करने के लिए सक्षम है कि क्या सहमति और संतुष्टि हुई थी और क्या दावेदार द्वारा 'कोई दावा नहीं/अदेयता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना स्वैच्छिक और किसी भी दबाव से मुक्त था या यह किसी प्रपीडन धोखाधड़ी या दबाव का परिणाम था।

16. उपरोक्त कानूनी स्थिति को सम्मुख रखते हुए, 'कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र/अदेयता प्रमाण पत्र' (No Claim Certificate/No Dues Certificate) जारी किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, दावेदार के दावे की विचारणीयता (tenability) से संबंधित पहले मुद्दे पर विचार किया जाना आवश्यक है। दावेदार ने मध्यस्थ के समक्ष दायर अपने दावा कथन (statement of claim) में, विशेष रूप से ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव का मामला प्रस्तुत किया था, जिसके कारण उसे अनिच्छा से 'अदेयता प्रमाण पत्र' जमा करना पड़ा। इस संबंध में दावा कथन में किए गए संगत अभिवचन (pleading) निम्नानुसार हैं:"

"2.2. दावेदार ने अपने दिनांक 19.4.2007 के पत्र के माध्यम से दो बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत कीं – कार्य के बड़े हिस्से के लिए 119.65 लाख रुपये की जो 02.07.2007 तक वैध थी, और कार्य के छोटे हिस्से के लिए 1.5 लाख



रुपये की जो 19.12.2007 तक वैध थी। दोनों बैंक गारंटियाँ इस उम्मीद में जमा की गई थीं कि प्रतिभूति जमा (Security Deposit) जारी कर दी जाएगी, जो उत्तरवादी द्वारा नहीं किया गया। उत्तरवादी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से दावेदार को वित्तीय रूप से परेशान किया और दावेदार पर अपने दिनांक 28.3.2007 के दावा पत्र को वापस लेने के लिए दबाव डाला, जिसके बिना उत्तरवादी बैंक गारंटी के एवज में उसकी प्रतिभूति जमा जारी नहीं करेगा।"

"2.3. दावेदार ने प्रपीडन में अपने पत्र दिनांक 25.4.2007 के माध्यम से अपने पहले के दावा पत्र दिनांक 28.3.2007 को वापस ले लिया, जिसमें यह कहा गया था कि उसका निपटान पक्षों के बीच सक्रिय विचाराधीन है। इस समय प्रतिवादी ने अपने दिनांक 11.5.2007 के पत्र के माध्यम से दावेदार को एक टेलेक्स संदेश भेजा, जिसमें विभाग के लिए आवश्यक "कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र" (No claim certificate) का पाठ संदेश देते हुए दिनांक 28.3.2007 के पत्र को वापस लेने के लिए कहा गया था। तदनुसार उसी दिन 11.5.2007 को दावेदार ने उक्त टेलेक्स संदेश के आधार पर "कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र" दिया।"

17. यहाँ अपीलकर्ता-कंपनी ने, तथापि, कई आधारों पर दावे का विरोध किया, जिसमें यह आपत्ति भी शामिल थी कि चूँकि दावेदार ने अपना 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate) प्रस्तुत कर दिया था और बातचीत के बाद पक्षों के बीच तय हुई राशि प्राप्त कर ली थी, इसलिए दावा अस्वीकार किए जाने योग्य था। इसलिए, यह मध्यस्थ द्वारा विचार और निर्णय के लिए एक मुद्दा बन गया। मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों, पत्राचार, स्थापित परिस्थितियों, दावेदार-ठेकेदार द्वारा सामना की गई वित्तीय तंगी, पक्षों के आचरण, (एवं अन्य) साक्ष्यों के आधार पर, मध्यस्थ ने अधिनिर्णय (Award) के पैरा 33 से 40 में, '11.5.2007 दिनांकित अदेयता प्रमाण पत्र' जमा करने के आधार पर दावे की पोषणीयता (maintainability) के मुद्दे पर, और साथ ही अपीलकर्ता-



कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रपीडन की युक्तियों (coercive tactics) के संबंध में विस्तृत निष्कर्ष दर्ज किए, कि दावेदार द्वारा दी गई सहमति प्रपीडक से प्रेरित थी और उसे सहमति देने के लिए मजबूर किया गया था। इस मुद्दे का निर्णय करते समय, मध्यस्थ ने ठेकेदार द्वारा अपने दावे में किए गए अभिवचनों की अस्पष्टता के संबंध में की गई प्रस्तुति पर विचार किया और निम्नलिखित विचार के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया:-

"33.00. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि दावा कथन में दावेदार द्वारा प्रपीडन और दबाव के संबंध में विवरण प्रस्तुत न करने से इस संबंध में उसकी अस्पष्ट और सामान्य निवेदन निरर्थक हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि चूँकि दावेदार ने पक्षों के बीच हुई उसके दावों की सहमति और संतुष्टि (accord and satisfaction) को रद्द करने की अनुतोष के लिए प्रार्थना नहीं की है, वह उसके द्वारा दावा की गई किसी भी अनुतोष पाने का हकदार नहीं है और उसकी दलीलें गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने योग्य नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व संदर्भित निर्णयों पर भी भरोसा किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उपरोक्त न्याय-निर्णय (case law) अधिकतर सिविल कार्यवाहियों से संबंधित हैं। इस संदर्भ में यह बताने की शायद ही आवश्यकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं। अतः, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभिवचनों (pleadings) आदि के कड़े नियम इन कार्यवाहियों में लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी द्वारा प्रयोग किए गए दबाव और प्रपीडन के संबंध में दावेदार की दलीलों पर, सभी अभिवचित तथ्यों और अभिलेख पर लाई गई सामग्री एवं परिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण अपनाते



हुए विचार करना होगा। मामले के उपरोक्त पहलू को, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें पक्षों के अभिवचन भी शामिल हैं, पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा।”

18. मध्यस्थ ने पक्षों के आचरण और विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर विचार किया। उस मौखिक साक्ष्य पर ध्यान दिया गया जिसमें दावेदार ने यह निर्दिष्ट किया था कि बाल्को, दावेदार द्वारा दी गई पूर्व सूचना को वापस लेने पर ही प्रतिभूति जमा को बैंक गारंटी में परिवर्तित करने के लिए तैयार था। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ बिना किसी आपत्ति या विरोध के, दावेदार ने सीधे 'अदेयता प्रमाण पत्र / कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र' प्रस्तुत किया हो। अभिलेख पर यह स्वीकृत स्थिति है कि, वास्तव में, दावेदार संतुष्ट नहीं था और इसलिए, उसने प्रारंभ में अपने अधिवक्ता के माध्यम से 28.3.2007 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें विवाद खड़ा करते हुए विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने की मांग की गई थी। उसे इस 28.3.2007 दिनांकित कानूनी नोटिस को वापस लेने के लिए क्यों मजबूर किया गया, इसका कारण उसके साक्ष्य में बताया गया था, जैसा कि ऊपर संदर्भित है। मध्यस्थ ने इस संबंध में संगत साक्ष्य पर भी निम्नानुसार विचार किया:-

“35.00.....उपरोक्त संदर्भ में, दावेदार ने प्रति-परीक्षा (cross-examination) में प्रश्न संख्या 118, 119 और 120 आदि के अपने उत्तरों में स्पष्ट किया है कि दावेदार द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दी गई दिनांक 28.3.2007 की पूर्व सूचना उसके द्वारा वापस ले ली गई थी क्योंकि दावेदार उत्तरवादी बाल्को (BALCO) से अपनी देय राशि प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, जिसे उत्तरवादी द्वारा रोक कर रखा गया था। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदार ने अपनी दिनांक 28.3.2007 की पूर्व सूचना को वापस लेने का विधिवत उचित स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि उसे उक्त सूचना वापस लेने के लिए



इसलिए मजबूर किया गया था क्योंकि प्रतिभूति जमा (Security Deposit) और दावों के मद में उसकी पर्याप्त राशि उत्तरवादी बाल्को द्वारा रोक ली गई थी और चूँकि वह उक्त राशि उत्तरवादी से वापस प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इसलिए, उसे उत्तरवादी के ऐसा करने के निर्देशों को मानने के लिए मजबूर किया गया था।”

19. मध्यस्थ ने स्थापित परिस्थितियों पर भी विचार किया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ठेकेदार ने दबाव में काम किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

"36.00. उपरोक्त परिस्थितियाँ यह प्रतीत कराती हैं कि दावेदार का यह निवेदन न्यायसंगत है कि उसे न केवल दिनांक 28.3.2007 के अपने पूर्व नोटिस को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि इसी तरह उसे 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' जारी करने के लिए भी विवश किया गया था, जिसे बाद में उसके द्वारा जारी किया गया, जबकि दावेदार के अतिरिक्त कार्य के बिल को कम कर दिया गया था और प्रतिवादी द्वारा उस पर एल.डी. (विलंब शुल्क) भी लगाया गया था। जैसा कि दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है, रिकॉर्ड पर रखी गई परिस्थितियाँ और दस्तावेज़ यह नहीं दर्शाते हैं कि उसने स्वतंत्र इच्छा से या स्वेच्छा से 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' जारी किया था या अतिरिक्त कार्य के एवज में कम राशि प्राप्त करने पर सहमत हुआ था या एल.डी. के किसी भी अधिरोपण पर सहमत हुआ था, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा उस पर लगाया गया है। उपरोक्त संदर्भ में, अनुलग्नक आर-2 (काउंटर-स्टेटमेंट) दिनांक 14.2.2007, जिस पर प्रतिवादी ने इस संदर्भ में भरोसा किया था, पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें दावेदार ने कथित तौर पर कहा है कि वह अनुबंध से छुटकारा पाने के लिए अतिरिक्त कार्य के लिए 76.95 लाख रुपये के बजाय 60 लाख रुपये स्वीकार करेगा। उसने इसमें आगे विशेष रूप





से बताया है कि वह किसी भी एल.डी. के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, यह प्रतीत होगा कि दावेदार ने किसी भी एल.डी. का भुगतान करने की अपनी देयता से इनकार किया है। यहां तक कि अतिरिक्त कार्य का भुगतान भी उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वीकार्य नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुबंध से संबंधित पूरी स्थिति से किसी तरह बाहर निकलना चाहता था। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि दावेदार तनाव में था और उसके द्वारा किए गए कार्य के बकाये को वसूल करने के साथ-साथ उसे देय राशि, जिसमें सुरक्षा जमा और उसके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी भी शामिल थी, को जारी करवाने के लिए वैध चिंता में था।"

20. अपीलकर्ता के आचरण से उत्पन्न होने वाली अन्य परिस्थितियाँ, जिसने ठेकेदार को दबाव और ज़बरदस्ती की स्थिति में डाल दिया, बिना उसकी स्वतंत्र इच्छा के, दबाव के आगे झुकने और कानूनी नोटिस वापस लेने के लिए आवेदन जमा करने के लिए, बाद में मध्यस्थ द्वारा इस प्रकार विचार किया गया:-

"37.00. यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि दावाकर्ता ने अपना 10 वां और प्री-फाइनल बिल 7 जुलाई 2006 को प्रस्तुत किया था (परिशिष्ट C-30, CD-11, पृष्ठ-164), फिर भी प्रतिवादी द्वारा इस मामले को लंबे समय तक लंबित रखा गया और जनवरी 2007 तक दावाकर्ता को भुगतान नहीं किया गया, जैसा कि दावाकर्ता के पत्र दिनांक 12.01.2007 (परिशिष्ट R-1, प्रतिवादी के प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 43-48) से स्पष्ट है, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि 10 वां एवं अंतिम बिल फिर से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही अतिरिक्त कार्य का बिल भी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मात्रा बिल में कई मदों को प्रतिवादी द्वारा बिना उचित कारण के कम कर दिया गया, जैसा कि प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 44 से 48, जो परिशिष्ट R-1 के अंतर्गत संलग्न हैं, से स्पष्ट होता



है। आगे यह भी प्रतीत होता है कि इसके बाद काफी समय बीत जाने के उपरांत प्रतिवादी ने दावाकर्ता के बकाया भुगतान के निपटान हेतु बैठकें आयोजित करनी शुरू कीं, जैसा कि 14 फरवरी 2007 की बैठक की कार्यवृत्त (परिशिष्ट R-2, प्रत्युत्तर विवरणी का पृष्ठ 49) से स्पष्ट है, जिसमें दावाकर्ता ने अपनी आपत्तियाँ दर्ज की थीं, जैसा कि उसमें दर्ज कार्यवृत्त से ज्ञात होता है।"

21. दावाकर्ता-ठेकेदार किस प्रकार असमान सौदेबाज़ी की स्थिति के कारण पीड़ित हो रहा था और किस प्रकार अपीलकर्ता कंपनी दंडात्मक क्षतिपूर्ति (liquidated damages) थोपने के संबंध में अनुचित लाभ उठा रही थी, इस पहलू पर मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया, जैसा कि नीचे उल्लेखित है:"

"38.00. उपरोक्त से यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रतिवादी ने यह कहा कि दावाकर्ता ने दंडात्मक क्षतिपूर्ति (एल.डी./LD) को स्वीकार करने के लिए अंततः सहमति दे दी थी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 23.03.2007 की बैठक की कार्यवृत्त (जो प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 53 पर है) से यह प्रतीत होता है कि एल.डी. का मुद्दा अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया था। यद्यपि बातचीत हुई थी, लेकिन उक्त कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि ये प्रस्ताव प्रबंधन के निर्णय पर निर्भर हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा यह जो कहा गया कि दंडात्मक क्षतिपूर्ति का मामला पक्षों के बीच अंतिम रूप से तय हो गया था, वह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यह अभी भी प्रतिवादी के प्रबंधन की स्वीकृति और पुष्टि के अधीन था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैठक में हुई चर्चा केवल अस्थायी थी और उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि प्रतिवादी की ओर से दावा करने का प्रयास किया गया है।"



"39.00. उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दावाकर्ता लगातार दंडात्मक क्षतिपूर्ति (LD) थोपे जाने का विरोध करता रहा, जैसा कि दिनांक 14 फरवरी 2007 की बैठक की कार्यवृत्त (परिशिष्ट R-2, प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 49, 50) में उसके द्वारा दर्ज नोट से स्पष्ट होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 22 मार्च 2007 की बैठक की कार्यवृत्त (प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 53) में यह दर्ज किया गया था कि दावाकर्ता का कार्य संतोषजनक पाया गया। उक्त कार्यवृत्त में प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह दर्ज किया गया कि दावाकर्ता द्वारा की गई कार्य की गुणवत्ता, शिल्पकौशल और प्रयुक्त सामग्री संतोषजनक थी, और समग्र निर्माण कार्य भी संतोषजनक पाया गया। इसमें आगे यह भी उल्लेख किया गया कि यद्यपि केवल 3 मीटर चौड़ाई के लिए वन विभाग की मंजूरी प्राप्त थी, फिर भी ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान वन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लिया, जिससे इच्छित चौड़ाई की सड़क का निर्माण संभव हो सका। इससे यह प्रतीत होता है कि दावाकर्ता लगातार अपने बिलों के भुगतान का अनुरोध करता रहा, फिर भी प्रतिवादी ने मामला लंबित रखा और दावाकर्ता के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। अंततः, जब दावाकर्ता को प्रतिवादी की शर्तों के अनुसार सहमत होने के लिए विवश किया गया, तभी अत्यंत विलंब के बाद बिलों का भुगतान किया गया।"

22. अधिनिर्णय के अनुच्छेद 40 में, पंच (Arbitrator) ने अपीलकर्ता कंपनी के व्यवहार की अधिनिर्णय पर विचार किया है, जिसमें दंडात्मक क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages) के मुद्दे पर निर्णय लेने में देरी करने और उसके बाद दावाकर्ता के प्रति निष्पक्ष तथा न्यायसंगत व्यवहार न करने का उल्लेख किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"40.00. उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दंडात्मक क्षतिपूर्ति (LD) का मुद्दा उस समय तुरंत नहीं उठाया गया जब ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया था, अर्थात् 2 जुलाई 2007 को, बल्कि यह मुद्दा काफी देर से



तब उठाया गया जब पूरा कार्य, जिसमें अतिरिक्त कार्य भी शामिल था, दावाकर्ता द्वारा पूर्ण कर लिया गया था। अतः यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने दावाकर्ता के प्रति निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया और उसके बकाया भुगतान को तब तक रोके रखा जब तक कि अंततः उसे विवश करके 16 अप्रैल 2007 को उस पर LD अधिरोपित किये जाने के लिए विवश नहीं कर लिया गया, जैसा कि परिशिष्ट R-4 (प्रत्युत्तर विवरणी के पृष्ठ 54) से स्पष्ट है।"

यह केवल अभिलेख में उपलब्ध सामग्री, स्थापित परिस्थितियों, पक्षकारों के व्यवहार विशेष रूप से असमान सौदेबाज़ी की स्थिति और अपीलकर्ता द्वारा अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने पर विस्तृत विचार करने के उपरांत ही था कि पंच (Arbitrator) ने अंततः निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचा:

"...अतः प्रतिवादी का यह कथन कि मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता, और यह कथित समझौता दावाकर्ता की स्वतंत्र इच्छा से हुआ हो, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, जैसा कि प्रतिवादी ने आरोपित किया है। इस स्थिति में, दावाकर्ता का यह आरोप कि समझौता उसकी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि उस पर लगातार कई बैठकों के माध्यम से दबाव डालकर जबरन करवाया गया, सत्य प्रतीत होता है। प्रतिवादी के उपरोक्त आचरण से यह स्पष्ट होता है कि दावाकर्ता की सहमति दबाव और दबदबे के कारण ली गई थी, और वह इसलिए सहमत हुआ क्योंकि वह चाहता था कि उसका भुगतान किया जाए, बकाया राशि उसे मिल जाए, और उसके बैंक गारंटी भी मुक्त किए जाएं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि न तो LD (दंडात्मक क्षतिपूर्ति) के मुद्दे पर और न ही किए गए कार्य के मूल्य पर कोई वास्तविक समझौता हुआ था।"



23. यह जो निष्कर्ष पंच (Arbitrator) द्वारा इस विवादास्पद और विशिष्ट मुद्दे पर अभिलिखित किया गया कि क्या वास्तव में 'सहमति और संतुष्टि' (accord and satisfaction) हुआ था, वह अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विस्तृत विचार पर आधारित है, और यह नहीं कहा जा सकता कि यह निष्कर्ष किसी भी प्रकार की विकृति (perversity), स्पष्ट गैरकानूनीता (patent illegality) या किसी अन्य ऐसी त्रुटि से ग्रस्त है जिससे पंचनिर्णय (Award) को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के योग्य ठहराया जा सके, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के **Associate Builders** मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए। प्रपीडन (coercion) और ज़बरदस्ती (duress) से संबंधित निष्कर्ष, तथा यह कि क्या वास्तव में 'सहमति और संतुष्टि' हुआ था, यह मूल रूप से एक तथ्यात्मक निष्कर्ष (finding of fact) है।
24. यह उल्लेखनीय है कि जब अंततः दावाकर्ता-ठेकेदार द्वारा विवाद उठाया गया और उसने विवाद का निपटान मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया, तब इस अपीलकर्ता कंपनी ने उस समय विवाद की मध्यस्थता योग्यता (arbitrability) का कोई प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि पंच नियुक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की। 16 फरवरी 2008 के पत्र द्वारा, अपीलकर्ता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक ने दावाकर्ता को सूचित किया कि इस मामले में मध्यस्थ के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। हालांकि, दावाकर्ता ने इस नियुक्ति को अनुबंध की धारा 17.1 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण इस न्यायालय में चुनौती दी, तब भी अपीलकर्ता ने मध्यस्थता योग्यता का मुद्दा नहीं उठाया बल्कि मध्यस्थ नियुक्ति के आदेश का समर्थन किया।
25. उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों, विशेष रूप से Reshmi Construction (पूर्वोक्त) के निर्णय के संदर्भ में, यह कानूनी स्थिति विवादित नहीं है कि यह प्रश्न कि क्या अनुबंध के तहत दावा पूर्ण और अंतिम रूप से निपटा दिया गया है, स्वयं एक विवाद है जो 'पर' (upon) या 'संबंधित' (in relation to) या 'जुड़ा हुआ' (in connection with) होता है, और ये आधार इतने



व्यापक हैं कि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। Bharat Heavy Electricals Ltd. (पूर्वोक्त) के मामले में भी यह माना गया कि समझौता और संतोष (accord and satisfaction) के माध्यम से अनुबंध का निर्वहन हुआ है या नहीं, यह एक अनुबंध से उत्पन्न विवाद है और इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। इसी प्रकार का दृष्टिकोण Jayesh Engineering Works बनाम New India Assurance Co. Ltd. (2000) 10 SCC 178 के मामले में भी लिया गया है, जिसमें यह माना गया कि कोई राशि देय है या नहीं और दावाकर्ता द्वारा किया गया दावा कितना उचित है, ये विषय मध्यस्थ द्वारा विचार किए जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त, जब ऐसे विवाद हों कि अनुबंध पूरी तरह से पूरा हुआ है या भुगतान पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में किया गया है, तो इन्हें भी मध्यस्थ द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए।

26. अतः यह निष्कर्ष निकालना होगा कि पंच (Arbitrator) के पास यह अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) था कि वह यह तय करे कि क्या वास्तव में समझौता और संतोष (accord and satisfaction) हुआ था और क्या 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' दबाव और ज़बरदस्ती (coercion and duress) का परिणाम था। वर्तमान मामले में यह मुद्दा वास्तव में उठाया गया था, जिस पर एक विवाद्यक विरचित किया गया और फिर पंच ने अभ्यावेदन (averment) और अभिलेख में मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का संदर्भ लेकर स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों से उचित निष्कर्ष निकालकर इसका निर्णय दिया। इस संबंध में दिया गया निर्णय न तो स्पष्ट गैरकानूनी (patent illegality) माना जा सकता है, न भारतीय कानून की मौलिक नीति (fundamental policy of Indian Law), न भारत के हित (Interest of India), न्याय (Justice), नैतिकता (Morality) या किसी अन्य आधार पर, जो कि पूर्व-संशोधित धारा 34 या संशोधित धारा 34 (2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा) में उल्लिखित हैं। ये शुद्ध तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं और अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को तथ्यात्मक अपील न्यायालय की भूमिका निभाने, अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि



पंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर संभव दृष्टिकोण है, तो अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत दिए गए अधिकार के प्रयोग में इस निर्णय में हस्तक्षेप करना कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है।

27. अगला विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या पंच द्वारा दावों संख्या 9, 10, 11, 12 को मंजूरी देने वाला निर्णय (Award) हस्तक्षेप के योग्य है। इस संदर्भ में, हमें निर्णय से यह मिलता है कि पंच ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि दावाकर्ता की संयंत्र और मशीनरी तथा कार्यबल निष्क्रिय रखे गए थे, सीधे ही प्रत्येक उपरोक्त शीर्षक पर प्रतीकात्मक राशि 2 लाख रुपये का अधिनिर्णय प्रदान किया, जो कुल मिलाकर 8 लाख रुपये होते हैं। दावों संख्या 9, 10, 11 एवं 12 पर निर्णय के अनुच्छेद 84 के तहत संबंधित भाग निम्नलिखित है।

"84.00..... दावा संख्या 9, 10, 11, 12: ये श्रम शक्ति के कम उपयोग, मशीनरी के कम उपयोग, ओवरहेड के कम उपयोग और उस विस्तारित अवधि के दौरान व्यावसायिक अवसर के नुकसान से संबंधित हैं, जब कार्य दावाकर्ता से कराया गया। उपरोक्त दावों को दावे की गई मात्रा तक सही ढंग से साबित नहीं किया गया है। इन दावों की राशि भी अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि दावाकर्ता को कम से कम कुछ कर्मचारी, मशीनरी और ओवरहेड बनाए रखने की आवश्यकता रही होगी, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ होगा। इसी प्रकार, उसने संभवतः कोई अन्य उपयोगी कार्य भी किया होगा जिससे उसे कुछ लाभ हुआ होगा। इसलिए, प्रत्येक उपरोक्त शीर्षक पर प्रतीकात्मक रूप से 2 लाख रुपये, कुल मिलाकर 8 लाख रुपये, दावों के उपरोक्त शीर्षकों पर प्रदान किए जाते हैं और इन्हें प्रतिवादी द्वारा दावाकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए।"

28. स्पष्ट रूप से, पंच ने केवल यह अनुमान लगाया कि दावाकर्ता-ठेकेदार को कम से कम कुछ कर्मचारियों, मशीनरी और ओवरहेड्स को बनाए रखना आवश्यक था, जिससे अतिरिक्त



खर्च हुआ होगा। यह भी देखा गया कि उसने संभवतः कुछ अन्य उपयोगी कार्य किए होंगे और उससे कुछ लाभ कमाया होगा।

29. हमारे विचार में, यह केवल अनुमान और कल्पना है, न कि दावों संख्या 9, 10, 11 और 12 के बारे में कोई विचारपूर्वक किया गया निष्कर्ष। पंच ने बिना दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य का विचार किए, यह मानकर प्रतीकात्मक राशि प्रदान की कि दावाकर्ता को कर्मचारियों, मशीनरी और ओवरहेड्स को बनाए रखना पड़ा होगा, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ होगा। इसके अलावा, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किसी भी याचिका या साक्ष्य पर विचार किए बिना, यह भी मान लिया गया कि ठेकेदार ने संभवतः कुछ अन्य उपयोगी कार्य किए होंगे और उनसे लाभ कमाया होगा। यह निष्कर्ष केवल विकृत (perverse) कहा जा सकता है। वास्तव में दावे संख्या 9, 10, 11 और 12 का कोई न्याय निर्णय नहीं किया गया है और पंच ने इन शीर्षकों पर 8 लाख रुपये अधिक प्रतीकात्मक राशि के रूप में दिया है, न कि कानून के तहत दावाकर्ता को ऐसी राशि मुआवजे के रूप में मिलने का विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हुए। Ferro Concrete Constructions (पूर्वोक्त) और Garware Shipping Corpn. Ltd. (पूर्वोक्त) के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, ये निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य पर विचार किए हुए हैं, अतः स्पष्ट रूप से विकृत हैं और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत हस्तक्षेप के योग्य हैं। इसलिए, इस सीमा तक आक्षेपित अधिनिर्णय (Award) अपास्त किया जाता है।

30. अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा मध्यस्थता योग्यता (arbitrability) से संबंधित है, जो ठेकेदार-दावाकर्ता द्वारा अनुबंध की निर्धारित अवधि के बाद किए गए कार्यों के लिए बढ़ाए गए/संशोधित दरों के अधिनिर्णय से जुड़ा है। जिस परिस्थिति में ठेकेदार को मूल अनुबंध के तहत कार्य निर्धारित अवधि के बाद पूरा करना पड़ा, उसे पंच ने अपने निर्णय में विस्तार से विचार किया है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। केवल यह प्रश्न बचता है कि क्या ठेकेदार को बढ़ाए गए या संशोधित दरों का हकदार माना जाएगा या नहीं। यद्यपि अपीलकर्ता कंपनी ने यह मुद्दा उठाया है कि पक्षों के बीच अनुबंध में ऐसी कोई विशिष्ट शर्त



नहीं है जो दावाकर्ता-ठेकेदार को सामान्य कार्य समय सीमा के बाहर किए गए कार्यों के लिए उच्चतर/संशोधित/बढ़ाए गए दरों का दावा करने का अधिकार देती हो, पंच का इस संबंध में निर्णय हस्तक्षेप के योग्य नहीं है, जैसा कि K.N. Sathyapalan (मृत) द्वारा LRs. बनाम राज्य केरल एवं अन्य, 2007 Arb.W.L.J. 1 (SC) के मामले के निर्णय में माना गया है, जिसमें इसी मुद्दे पर विचार किया गया और निम्नलिखित उत्तर दिया गया।

"33. वह प्रश्न जिसका हमें इस अपील में उत्तर देना है, यह है कि मूल अनुबंध में कोई मूल्य वृद्धि (price escalation) की शर्त न होने और पूरक अनुबंध में इसके विपरीत कोई विशेष निषेध न होने की स्थिति में, क्या अपीलकर्ता ने लागत वृद्धि के आधार पर कोई दावा कर सकता है, और क्या पंच ने ऐसे दावों को मंजूर करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया।"

"34. सामान्यतः, पक्ष अनुबंध में सहमत शर्तों के बंधे होते हैं, लेकिन यदि अनुबंध के किसी एक पक्ष को अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता होती है, जिससे दूसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य पर सीधे प्रभाव पड़ता है, तो पंच के पास यह अधिकार होता है कि वह दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की असमर्थता के कारण हुए अतिरिक्त खर्च के लिए मुआवजा प्रदान करे। यही इस प्रकार के मामलों की विशिष्ट विशेषता है, जैसा कि M/s. Alopi Parshad के मामले (पूर्वोक्त) और Patel Engineering के मामले (पूर्वोक्त) में भी कहा गया है। जैसा कि श्री डेव ने बताया, इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने P.M. Paul के मामले (पूर्वोक्त) में स्वीकार किया था, जहाँ इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भवन के निर्माण में हुई देरी और उसकी परिणति के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त विद्वान न्यायाधीश के निष्कर्षों के आधार पर, इस न्यायालय ने अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान सामग्री के मूल्य और मजदूरी तथा परिवहन लागत में वृद्धि



के कारण पंच द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी, भले ही कोई मूल्य वृद्धि की शर्त न हो।"

"35. यह सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा टी.पी. जॉर्ज के मामले (पूर्वोक्त) में पुनः दोहराया गया था।"

"36. हमने जानबूझकर वह पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिसमें पंच ने अपना निर्णय दिया, ताकि उन दावों की प्रामाणिकता और/या वैधता की जांच की जा सके जिन्हें पंच ने मंजूर किया था। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निर्धारित ग्यारह महीनों की अवधि के भीतर कार्य पूरा करने से रोका गया था, और यह देरी उस समय रोकी जा सकती थी यदि राज्य सरकार ने कार्य स्थल पर उत्पन्न हुए कानून-व्यवस्था के समस्या को नियंत्रण में लिया होता। यह भी स्पष्ट है कि मन्नडी के विभागीय खदान में उपलब्ध होने वाला मलबा और धातु उस स्थान से दोगुनी दूरी पर स्थित खदानों से प्राप्त करना पड़ा, जिससे परिवहन शुल्क भी दोगुना हो गया। यहां तक कि अतिरिक्त मिट्टी डालने के लिए स्थान भी प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण अपीलकर्ता को अतिरिक्त मिट्टी एक दूरस्थ स्थान पर डालनी पड़ी, जिससे अतिरिक्त खर्चा हुआ।"

"37. उपरोक्त परिस्थितियों में, पंच ने लागत वृद्धि के कारण कुछ दावों को मंजूर करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है, जो कि विस्तारित अवधि के दौरान कार्य के निष्पादन से संबंधित थे। हमारे निर्णय में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनुबंध की शर्तों और पक्षों के बीच निष्पादित पूरक समझौते की कठोर व्याख्या पर आधारित था, जो घटनाओं के क्रम द्वारा उचित नहीं था।"

31. एक मुद्दा यह भी उठाया गया है कि अधिनिर्णय, जहां दावा संख्या 4 बैंक गारंटी की वापसी से संबंधित है, यह प्रस्तुत किया गया कि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने



में विफल रहा, इसलिए अनुबंध की शर्तें अपीलकर्ता को 1,50,000 रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने का अधिकार देती हैं।"

"हालांकि, चूंकि अपीलकर्ता-कंपनी ने पंच के निर्णय के पैराग्राफ 42 से 51 तक के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है, जिसमें पंच ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि देरी के लिए ठेकेदार नहीं बल्कि अपीलकर्ता-कंपनी जिम्मेदार थी, इसलिए बैंक गारंटी को लागू करना कानून के खिलाफ पाया गया और वापसी के निर्देश दिए गए। अतः इस आधार को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा सही ढंग से अस्वीकार किया गया।"

32. हालांकि, हमें लगता है कि पंच ने प्रतिदावा में उठाए गए परिसमाप्त क्षति के दावे को बिना विस्तृत निष्कर्ष दर्ज किए अस्वीकार कर दिया है, लेकिन विभिन्न शीर्षकों पर निर्णय करते हुए यह निष्कर्ष दिया गया है कि कार्य में देरी ठेकेदार-दावेदार की वजह से नहीं बल्कि केवल अपीलकर्ता की वजह से हुई थी, और उसे कार्य में देरी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, इसलिए ठेकेदार के अनुबंध की क्लॉज-13 के तहत परिसमाप्त क्षति का दावा भी अस्वीकृत हो जाता है। इस संबंध में, पक्षों के बीच अनुबंध की क्लॉज-13 उल्लेखनीय है:"

"13.0. परिनिर्धारित नुकसान:- यदि ठेकेदार, मालिक द्वारा लिखित रूप में सूचित की गई निर्धारित तारीखों या उस अवधि के विस्तार के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार को मालिकों को प्रत्येक दिन के लिए कुल कार्य मूल्य (ठेका मूल्य) के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से हर्जाना (परिनिर्धारित क्षति) देना होगा जब तक कार्य अधूरा रहेगा। यह हर्जाना दंड के रूप में नहीं, बल्कि मुआवजे के रूप में होगा। यह भी शर्त है कि इस मुआवजे की राशि ठेका मूल्य का 10% से अधिक नहीं होगी।

अपने किसी भी कानूनी अधिकारों को प्रभावित किए बिना, मालिकों को यह अधिकार होगा कि वे उक्त मुआवजे/हानि की राशि को ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से वसूल कर सकें। इस



मुआवजे/हानि का भुगतान या कटौती ठेकेदार को कार्य पूरा करने के अपने दायित्वों या अनुबंध के तहत उसके अन्य दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी। यदि ठेकेदार असफल रहता है, तो इंजीनियर की पूर्ण विवेकाधिकार पर, कार्य को किसी अन्य एजेंसी द्वारा ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर पूरा करने का आदेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार को न्यूनतम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना दी गई हो।"

33. स्पष्ट रूप से परिनिर्धारित नुकसान के दावे को स्थापित करने के लिए, अपीलकर्ता-कंपनी को यह साबित करना आवश्यक था कि निर्धारित समय सीमा के बाद कार्य में हुई देरी ठेकेदार की चूक या लापरवाही के कारण हुई थी। लेकिन पंच द्वारा दर्ज निष्कर्ष इसके विपरीत है कि देरी उन परिस्थितियों के कारण हुई जो अपीलकर्ता द्वारा पैदा की गई थीं और देरी के कोई भी कारण दावेदार-ठेकेदार के कारण नहीं थे। इसलिए, इस संदर्भ में भी, अधिनिर्णय में हस्तक्षेप कर कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती।
34. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से केवल इस सीमा तक मंजूर की जाती है कि दावा संख्या 9, 10, 11, 12 पर 8 लाख रुपये का अधिनिर्णय अपास्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



2018:CGHC:32157-DB

-40-

